कृषि विभाग का दावा : करनाल में 70 प्रतिशत घटे पराली जलाने के मामले

करनाल (के सी आर्य) कृषि विभाग का दावा पिछले साल के मुकाबले करनाल में 70 प्रतिशत तक घटे पराली जलाने के मामले, पराली जलाने वाले किसानों से कृषि विभाग ने 4.85 लाख का जुर्माना वसूला, जुर्माना नही भरने की एवज में एक किसान पर कृषि विभाग ने मामला दर्ज कराया, कृषि अधिकारी का कहना है कि पंजाब से इस बार पराली जलाने के अधिक मामले सामने आए हैं।

कृषि अधिकारियों ने दावा कि किया है कि पिछले साल की अपेक्षा पराली जलाने के मामलों में भारी कमी आई है। पिछले साल एक नवंबर तक जहां 740 केस सामने आए थे, वहीं अब तक करीब 252 केस सामने आए है। जिसकी वजह से एयर क्वालिटी एडेक्स भी काफी ठीक रहा। अब तक करीब 70 प्रतिशत केस कम सामने आए है।

कृषि अधिकारी ने बताया कि कृषि विभाग द्वारा लगातार किसानों को जागरूक किया जाता रहा, गांव दर गांव में किसानों को पराली जलाने के नुकसान के बारे में बताया गया, इसके अलावा जो किसान समझाने के बाद भी नहीं माने तो उनके खिलाफ सख्ती बरती गई। पराली जलाने वाले किसानों में अगर पूरे हरियाणा की बात करें तो 25 प्रतिशत केस कम दर्ज किए गए। इस तरह से घटे पराली जलाने के मामले उप कृषि निदेशक डॉ आदित्य डबास ने बताया कि कृषि विभाग के अधिकारियों ने दिन रात एक किया है, जिसके परिणाम स्वरूप पराली जलाने के मामले में कमी आई है। सरकार ने उन किसानों को प्रति एकड़ एक हजार रुपए की धनराशि दी है, जिन किसानों ने पराली को खेत से बाहर निकाला है या फिर पराली को खेत में मिलाया है। इसके अलावा विभाग द्वारा किसानों को 250 बेलर मशीन, फ्री डि कंपोजर ओर करीब 7 हजार 500 कृषि उपकरण दिए है, जिनकी मदद से किसानों ने पराली प्रबंधन किया है।

पराली जलाने से हो जाती थी आबो हवा खराब

किसानों द्वारा अगली फसल लगाने की जल्दबादी में फसल अवशेषों को आग के हवाले कर देते थे, जिससे आबो हवा अशुद्व हो जाती थी। वायु की गुणवत्ता इतनी खराब हो जाती थी कि लोगों को सांस लेना भी मुश्किल हो जाती था। सबसे ज्यादा परेशानी अस्थमा के मरीजों को उठानी पड़ती थी, पराली जलाने से निकले जहरीले धुएं की वजह से अस्थमा के मरीजों को अस्पताल में भर्ती होने की नौबत तक आ जाती थी। लेकिन इस बार पराली जलाने की घटनाओं में काफी कमी है। जो कृषि विभाग के साथ-साथ प्रशासन के लिए बड़ी राहत की बात है। उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में फसल अवशेष जलाने की घटनाओं में ओर कमी आएगी।

1 करोड़ 10 लाख लूटने के बाद जेई दीपक की हत्या, नहर से शव बरामद

करनाल (के सी आर्य)। गांव गगसीना निवासी दीपक जेई (पीडब्ल्यूडी) एक करोड़ 10 लाख के साथ 2 नवम्बर को पंचकूला से चला था। किसका पैसा था कुछ नही पता, कार नहर किनारे तो मिल गई जिसका शीशा टूटा हुआ था और कैश नदारद था।

परिजनों को उसकी गुमशुदगी पर शक हुआ तो उन्होंने मुनक के पास सड़क पर जाम लगा दिया और पुलिस से मामले की शीघ्र तफ्तीश करने का दबाव बनाया। पुलिस इससे पहले उसको ढूंढ पाती कि दिनांक 4 तारीख को उसकी लाश नहर से बरामद हो गयी।

जानकारों का कहना है कि नौकरी के साथ-साथ दीपक भाजपा के किसान मोर्चा की कोई छोटी-मोटी नेतागिरी भी करता था। समझा जाता है कि यह पैसा या तो हवाला का है अथवा जुएं, सट्टे के लेन-देन का है। पुलिस गुत्थी सुलझाने में व्यस्त है।

फीस बढ़ोतरी के खिलाफ मेडिकल छात्रों का संघर्ष

करनाल (के सी आर्य) नीट में बेहतर रैंक लाने वाले विद्यार्थी को हरियाणा के मेडिकल कालेजों में दस लाख रुपये फीस वसूलने के विरोध में हस्ताक्षर अभियान के साथ-साथ करनाल के अम्बेडकर चौक तक रोष व्यक्त किया गया। विरोध के दूसरे दिन कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कालेज के स्टूडेंट्स ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए प्रदेश सरकार से नई नीति को रद्द करने की मांग की। आरोप है कि हरियाणा के सरकारी मेडिकल कालेजों में अधिक फीस के कारण स्टूडेंट्स दूसरे राज्यों में दाखिला लेना पसंद कर रहे हैं। इसके कारण हुई खाली सीटों पर कम अंकों वाले वे छात्र दाखिला ले रहे हैं जिनके पास मोटी फीस देने को है।

50 हजार रुपये की जगह दस लाख रुपये जमा करवाने होंगे , रोष जता रहे स्टूडेंट्स का कहना है कि वर्ष-2020 में दाखिले के दौरान सालाना 50 हजार रुपये फीस जमा करवानी होती थी। इसके अलावा सात साल नौकरी करने या 40 लाख रुपये जमा करवाने का शपथ पत्र दिया गया था। वर्ष-2021 सत्र में भी नौकरी की गारंटी मेडिकल स्टूडेंट को नहीं दी गई। वर्ष-2022 में नई पालिसी के तहत स्टूडेंट्स से दस लाख रुपये जमा करवाने के लिए कहा गया है और शपथ पत्र में लिख कर देना होगा कि वे इस पालिसी को कोर्ट में चुनौती भी नहीं दे सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए 10 लाख रुपए जमा करवाना मुश्किल है।

प्रदेश के टापर दूसरे राज्यों में दाखिले के इच्छुक

पालिसी के विरोध में स्टूडेंट हिमांशी, यशिका, सत्यपाल ने बताया कि सरकार की ओर से एमबीबीएस करने के इच्छुक विद्यार्थियों से मोटी फीस जमा करवाने के नए फैसले के कारण नीट के टापर दूसरे राज्यों में पढ़ाई के लिए जाने लगे हैं। दूसरे राज्यों में निजी कालेज में छह लाख रुपये में

शिक्षा मिल रही है जबकि हरियाणा में दस लाख रुपये जमा करवाए जा रहे है। आरोप है कि सरकार के इस फैसले से किसान-मजदूर के बच्चों से एमबीबीएस की पढ़ाई दूर हो जाएगी और नीट में टाप रैंक लाने के बावजूद वे हरियाणा में अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी नहीं कर सकेंगे इसलिए स्टूडेट्स का आरोप है कि इस हिसाब से कोर्स की कुल फीस 45 लाख रुपये होगी।

वर्ष-2020 व 2021 में दाखिले के दौरान कर्ज लेने की नौबत नहीं आई क्योंकि अब वर्ष-2022 में दाखिले में फीस देने या कर्ज लेने के लिए कह रहे हैं। इसके विरोध में आंदोलन वर्ष-2020 से चल रहा है और एक जनहित याचिका भी उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में विचाराधीन है। कालेज फीस के अलावा विद्यार्थियों को हास्टल शुल्क, मैस बिल, किताबें और स्टेशनरी के लिए भी भुगतान करना पड़ता है। जो हर साल लगभग 70 से 80 हजार रुपये बन जाता है। शांतिपूर्ण रोष के दौरान स्टूडेंट्स ने समानता के कानून का भी जिक्र किया।

खट्टर सरकार द्वारा बढ़ाई गयी यह फीस न केवल डॉक्टरी पढ़ने वालों पर एक करारा हमला है बल्कि आम जनता को भी चिकित्सा सेवा से वंचित करने का षड़यंत्र है। करोड़ों रूपए खर्च करके जो डॉक्टर बनेगा वह जनता का गला नहीं काटेगा तो क्या करेगा? डॉक्टरी पढ़कर आने वाले को जो वेतन सरकार देती है उससे तो पढ़ाई की लागत का ब्याज भी नहीं निकल पायेगा। यह हालत तो तब है जब सरकारी नौकरी मिल जाये वरना तो डॉक्टरों को नौकरी के लिए भटकना ही पड़ेगा।

इसलिए मेडिकल छात्रों के इस आंदोलन को जनता अपना आंदोलन समझकर इसके साथ जुड़े। सरकारी आश्वासनों व अदालतों के भरोसे न रहकर संघर्ष को तेज करें।

भाजपाइयों के भाषण में स्पष्ट नजर आई हार की बौखलाहट- हुड्डा

करनाल। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की टिप्पणियों का जवाब दिया है। हुड्डा ने कहा कि आदमपुर रैली के मंच से भाजपा नेताओं में हार की निराशा स्पष्ट नजर आई। भाजपाई रैली से स्पष्ट हो गया कि सरकार के पास आदमपुर में गिनवाने लायक एक भी काम नहीं है। सरकार ने मान लिया कि उसने 8 साल में आदमपुर की घोर अनदेखी की और विकास में भेदभाव किया।

भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि अपने भाषणों में भाजपा नेता खुद मान रहे हैं कि बीजेपी के पास बस 2 साल का कार्यकाल बाकी है। इसलिए वह 2 साल की सरकार का हवाला देकर लोगों से वोट मांग रहे हैं। यानी खुद भाजपाई मान रहे हैं कि वो 2 साल बाद सत्ता से बाहर हो रहे हैं और भविष्य में कांग्रेस सरकार बनने जा रही है। इसलिए आदमपुर से बीजेपी की विदाई की शुरुआत होगी। यहां की जनता आने वाली सरकार में अभी से भागीदारी करेगी। मैंने आदमपुर का हाथ कस के पकड़ लिया है, इसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। इसबार आदमपुर की जनता एक वोट से दो विधायक बनाने का काम करेगी- एक जयप्रकाश और दूसरा भूपेंद्र सिंह हुड्डा।

हुड्डा ने कहा कि लगातार कांग्रेस का कुनबा मजबूत होता जा रहा है। आदमपुर से बीजेपी के लगभग तमाम बड़े नेता कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। लेकिन मुख्यमंत्री दावा करते हैं कि कांग्रेस कमजोर है। हुड्डा ने पूछा कि अगर कांग्रेस कमजोर है तो सत्ता पक्ष को छोड़कर बीजेपी के दर्जनभर पूर्व विधायक कांग्रेस में क्यों शामिल हुए? मुख्यमंत्री को पता होना चाहिए कि पिछले चंद महीने में प्रदेशभर से सैंकड़ों भाजपा नेता व कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं।

मुख्यमंत्री द्वारा 3सी और 5एस वाले दावे पर बोलते हुए हुड्डा ने कहा कि खुद सरकारी आंकड़े बताते हैं कि बीजेपी सरकार के 8 साल में क्राइम, कास्ट और करप्शन में ऐतिहासिक बढ़ोत्तरी हुई है। इसी तरह यह सरकार बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, नशा, अपराध और महंगाई को बढ़ाने के 5 सूत्रीय एजेंडा पर आगे बढ़ रही है।

इस सरकार ने अपने कार्यकाल में हर वर्ग को प्रताड़ित करने का काम किया। आदमपुर समेत पूरे हरियाणा को याद है कि मौजूदा सरकार ने एमएसपी मांग रहे किसानों पर लाठियां बरसाई, रोजगार मांग रहे युवाओं पर वाटर कैनन छोड़ी, पेंशन मांग रहे बुजुर्गों को थाने में बैठाया, टीचर मांग रहे बच्चों को खून के आंसू रुलाया, कर्मचारियों को पुरानी पेंशन के लिए तरसाया और आढ़ती-व्यापारियों को बार-बार हड़ताल करने के लिए मजबूर किया। इसलिए हर तबका वोट के जरिए बीजेपी को सबक सिखाना चाहता है।

नेता प्रतिपक्ष ने आगे पूछा कि अगर बीजेपी दलित और पिछड़ों की शुभचिंतक है तो उसने उन 5000 सरकारी स्कूलों को क्यों बंद किया, जहां पर गरीब, किसान, दलित और पिछड़ों के बच्चे सबसे ज्यादा पढ़ते हैं? बीजेपी सरकार ने गरीब, दलित और पिछड़े वर्ग के बच्चों का वजीफा क्यों बंद किया? क्यों इस सरकार ने इन वर्गों के लाखों बेसहारा बुजुर्गों की पेंशन खत्म कर दी? क्यों सरकारी नौकरियां खत्म कर कौशल निगम शुरू किया गया? कौशल निगम की नौकरियों में दलित और पिछड़ों को आरक्षण क्यों नहीं दिया गया?

क्यों सरकार ने सत्ता में आते ही कांग्रेस की चलाई गई 100-100 गज के प्लॉट आवंटन की योजना को बंद किया? इस सरकार ने पिछड़ा वर्ग से आरक्षण छीनने के लिए क्रीमी लेयर की लिमिट को 8 से घटाकर 6 लाख क्यों किया?

आखिर बीजेपी जातीय जनगणना से क्यों भाग रही है, जबकि कांग्रेस इसका समर्थन करती है। जाहिर है सरकार के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं है इसलिए उसके नेता बेबुनियाद और हवा-हवाई बातों के सहारे जनता को बरगलाना चाहते हैं। लेकिन जनता बीजेपी को वोट की चोट से सबक सिखाने का काम करेगी।